एकात्म भारत

वैशाख शुक्ल पक्ष, प्रथमा, शनिवार, विक्रम संवत् 2077

इदं राष्ट्राय इदं न मम्

23 मई 2020

e-paper : www.ekatmabharat.

बाबर नाम का आदमी कभी अयोध्या नहीं आया

श्री राम जन्मभूमि के अवशेषों के आधार पर बोले पूर्व सासंद और संत रामविलास वेदांती

अयोध्या

अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिलने के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भाजपा के पूर्व सांसद और संत राम विलास वेदांती ने कहा है कि स्पष्ट हो गया है कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति कभी अयोध्या नहीं आया था।

संत राम विलास वेदांती राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वहां पुरातत्व विभाग को जन्मभूमि से राम मंदिर संबंधित चक्र, संख, गदा, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, 'ॐ' ,मृत कलश, सारी मंदिर की आकृति के बनावट के पत्थर मिले थे, उन प्रमाणों को भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने यह कहकर नकार दिया कि विश्व हिंदू परिषद वालों ने रखा है। अब जब खुदाई प्रारंभ हो गई है और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं अब उनको तो विश्व हिंदू परिषद गाड़ नहीं रही है और ना ही विश्व हिंदू परिषद उखाड़ रही है, तो जो वहां स्वाभाविक था वहीं दिखाई दिया है।

वेदांती ने जोर देकर कहा कि कभी किसी कीमत पर कोई भी बाबर नाम का व्यक्ति नहीं आया। अयोध्या में बाबर के नाम पर न कोई गली ना कोई मोहल्ला ना कोई घाट ना कोई गांव था फिर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कैसे बनीं? इसीलिए मैंने हाईकोर्ट की गवाही

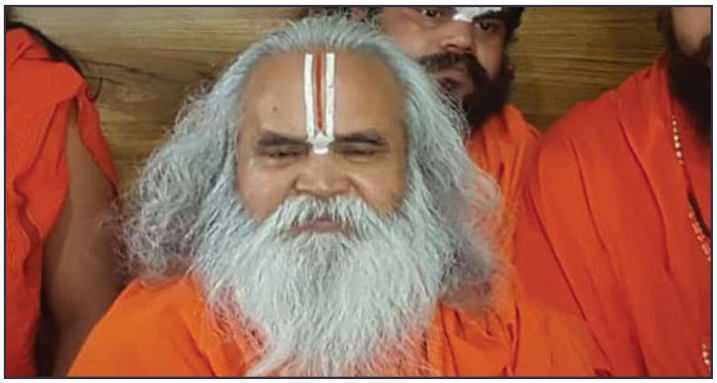

में कहा था कि वहां पर मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है। वहां रामलला विराजमान है।

उन्होंने कहा कि खंडहर कभी भी टूटकर गिर सकता है इसलिए हमने सितंबर 1992 को कारसेवकों को बुलाकर ढांचे को तुड़वाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली थी। आज दुनिया के सामने सारे मुसलमानों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको देख लें और देख कर के दुनिया के मुसलमानों को बता दें कि इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं और ना ही मस्जिद का कोई चिन्ह मिला है। वहां तो बस भगवान श्री राम के चिन्ह मिले हैं। वहां केवल मंदिर के चिन्ह मिले हैं, पुरातत्व विभाग ने भी इसको देखा है। हम सब लोगों ने उसको देखा है। इसलिए संपूर्ण विश्व के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद रही नहीं गया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पूर्व सांसद और संत राम विलास वेदांती ने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग से लेकर विश्व हिंदू परिषद, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नया ट्रस्ट बनाकर भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण की योजना को प्रारंभ कर दिया है। बता दें कि खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तम्भ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तम्भ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला है।

महात्मा बुद्ध सनातन धर्म के हिस्से हैं, कांग्रेसी उदित राज को कांग्रेसी नेता की सलाह

समतलीकरण के दौरान श्री राम जन्मभूमि से मिले अवशेषों को बौद्ध धर्म से जुड़ा बता कर इस मामले में अध्ययन किए जाने की मांग करने वाले पूर्व भाजपा सांसद और वर्तमान कांग्रेस नेता उदित राज की उन्हीं की पार्टी के नेता राजीव त्यागी ने क्लास ले ली। त्यागी ने उदितराज को कहा कि महात्मा बुद्ध भी सनातन धर्म का हिस्सा थे।

आप पहले अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए। त्यागी ने उदित राज के ट्वीट का जवाब देते हुए मेरे प्रभु श्रीराम त्रेता युग में हुए और बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और निर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ। एक समय था सनातन धर्म कई बार आक्रांत किया गया और मंदिरों पर आक्रमण हुए। और महात्मा बुद्ध भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं। कृपया अपना ज्ञान दुरुस्त करें और मिथ्या वचन करने से बचें।

सोशल वोकल

Ram Anoop Dwivedi

@Anoop1255

"चीजों को नजरअंदाज करने की काबिलियत हासिल करना मन की शांति प्राप्त करने का उत्तम तरीका है।"
- अज्ञात

"Learning to ignore things is one of the great paths to inner peace."
- Anonymous

राम अनूप द्विवेदी वाराणासी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ज्यादातर सकारात्मक ट्वीट्स करते हैं।

भारत पर इस्लामोफोबिया के आरोप गलत

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान से बोला मालदीव

नई दिल्ली

पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आगे भारत को कठघरे में खड़ा करने के प्रयास पर मुंह की खानी पड़ी है। इस बार भारत के पड़ोसी मालदीव ने उसे आईना दिखाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह घटना ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की वर्चुअल मीटिंग में हई। इसमें पाकिस्तान ने भारत में इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया तो इस पर मालदीव ने कहा कि वो भारत के खिलाफ किसी एक्शन का समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद भारतीय राजदूत ने सेक्युलर सोच और विविधता वाले भारतीय समाज के समर्थन के लिए मालदीव को धन्यवाद किया है।

ओआईसी की बैठक में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिल्मिजा हुसैन ने कहा, भारत बहुसांस्कृतिक समाज में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ

लोगों द्वारा फैलाई गई बातें भारत के 130 करोड़ लोगों की राय नहीं समझी जा सकती हैं। ऐसे में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना गलत है। ये तथ्यात्मक रूप से भी गलत है.

57 सदस्यीय समूह की ओआईसी की बैठक में हुसैन ने कहा, मालदीव ओआईसी में ऐसे किसी एक्शन का समर्थन नहीं करेगा, जिसमें भारत को निशाना बनाया जाएगा। मालदीव ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने सऊदी अरब, यूएई, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और मॉरीशस जैसे कुछ सबसे बड़े ओआईसी सदस्यों के साथ मजबूत एलायंस बनाया है। हुसैन ने कहा कि भारतीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है।

ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने पहले कहा था, भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद मालदीव ने अपने आधिकारिक बयान में दुनिया में बढ़ती नफरत की आलोचना की और भारत पर लगे इस्लामोफोबिया के आरोप को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया।

मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिल्मिजा हुसैन ने अपने बयान में कहा, "दुनिया में नफरत की संस्कृति बढ़ती जा रही है। मालदीव दुनिया में कहीं भी इस तरह की कार्रवाइ के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, जिसमें इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिया या हिंसा के किसी भी रूप में राजनीतिक या किसी अन्य एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है। लेकिन किसी विशिष्ट देश पर आरोप लगाना वास्तविक मुद्दे को दरकिनार करने जैसा होगा।"

घर लौटे श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग देने में जुटेंगे संघ के अनुषांगिक संगठन

झारखंड में विकास भारती जैसी संस्था काम कर रही है। वहीं अन्य राज्यों में अन्य संस्थाओं के माध्यम से यह काम होगा। इनमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान और सेवा भारती भी काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

नई दिल्ली

कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन ने मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली और शहरों बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गावों को लौट रहे हैं। पर गांव में भी कुछ समय बाद उनके सामने फिर रोजगार की समस्या उठ खड़ी होगी। इसी के मद्देनजर अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आगे आया है। संघ अपने सहयोगी संगठनों के जरिए घर लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। संघ पदाधिकारियों ने अपने अनुषांगिक संगठनों को तैयारी करने के लिए कहा है।

नाम न छापने के अनुरोध पर दि प्रिंट से संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, 'अलग-अलग राज्यों में हमने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि मजदूरों के रोजगार को लेकर क्या-क्या किया जा सकता है। मजदूरों की स्किल के हिसाब से अगर किसी छोटी मोटी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो वह भी कराई जा सकती है। इसी दिशा में काम भी शुरू कर दिया है।' उन्होंने कहा, 'हर राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर की तरफ गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में

मजदूर अपने घरों को लौटे हैं। हमारी कोशिश है कि इन को लोगों दोबारा रोजगार से जोड़ें। कुछ राज्यों में यह संभावना ज्यादा बनेगी तो कुछ राज्यों में कम। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ज्यादा दूर गए बगैर मजदूरों को कैसे स्थानीय रोजगार से जोड़ा जा सकता है। मजदूरों से एक फार्म के जरिए या सीधे उनसे पूछेंगे कि उनकी कुशलता किस क्षेत्र में है। वे यहां रहना चाहते हैं या बाहर काम के लिए दोबारा जाना चाहते हैं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।'

पदाधिकारी ने आगे कहा, 'झारखंड में विकास भारती जैसी संस्था काम कर रही है। वहीं अन्य राज्यों में अन्य संस्थाओं के माध्यम से यह काम होगा। इनमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान और सेवा भारती भी काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी जैसा प्रारूप तैयार होगा, उसके हिसाब से काम करना शुरू होगा।'

'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की ओर कदम

संघ के सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने अपने उद्बोधन में कोरोना महामारी से निपटने के बीच स्वदेशी माध्यमों को अपनाने कि बात पर जोर दिया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी स्वदेशी अपनाने की बात पर बल देते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का देशवासियों से आग्रह किया था।

दरअसल संघ और सरकार का स्वदेशी अपनाओ की बात आत्मनिर्भर भारत का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। इसमें स्पष्ट है कि विरोध किसी का न हो और भारतीय उत्पादों को अधिक संख्या में प्रोत्साहन मिले। स्वदेशी जागरण मंच भी इस बात को प्रमुखता से रखते हुए अब पूरे देश में स्वदेशी अपनाओ का जागरण शुरू कर चुका है। जहां तक बात है प्रवासी मजदूरों के स्थानीय रोजगार की तो संघ से लेकर सरकार के प्रयास आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम माने जा रहे हैं।

घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर रही सरकार

कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन के बाद लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उनकी निगरानी रखने और रिकार्ड रखने का एक समाधान खोजा है। गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है।

इसके माध्यम से घरों को लौट रहे मजदूरों पर निगरानी रखी जा सकेगी। वहीं उनकी यात्रा को भी आसान बनाया जा सकेगा। इस पोर्टल का निर्माण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया है। यह पोर्टल केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगा।

दि प्रिंट से साभार

योगी ने खुद तुड़वाई अपने मठ की दुकानें

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकबार फिर उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट के लिए अपने ही गोरखनाथ मंदिर की दीवाल ढहा दी है।

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बताया कि उनके लिए फर्ज से पहले कुछ नहीं है। गोरखपुर से सोनौली के लिए बन रहे फोरलेन के लिए उन्होंने गोरखनाथ मंदिर की दीवार को ढहा कर औरों के लिए एक नया मानक तय कर दिया।

सीएम ने इसके साथ ही एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि विकास के रास्ते में मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारा, मजार हो या अन्य कोई धार्मिक स्थल, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी नजीर पेश की है। इसके पहले लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर उन्होंने बताया कि राजधर्म क्या होता है, एक बड़े परिवार का मुखिया होने का क्या मतलब होता है। गोरखपुर फोरलेन के रास्ते में आने वाले किसी और को अपने मकान और दुकान के ध्वस्तीकरण पर किसी को आपत्ति न हो इसके लिए इसके लिए मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने मंदिर की दीवार को ढहाने का आदेश दे दिया। बाकियों की दुकान और मकान के ध्वस्त होने पर वाया गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला, मोहद्दीपुर, कूड़ाघाट और नंदानगर होते हुए एयरपोर्ट तक का आना-जाना आसान हो जाएगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री होने के बाद और बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ बार-बार यह कहते रहे हैं कि जनहित और विकास एक दूसरे के पूरक हैं।

इसमें किसी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं है। लोक कल्याण के लिए विकास हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है। गोरखपुर के मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक करीब 17 किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण में आड़े आ रहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर से सटी करीब 100 दुकानों को तीन दिन में ध्वस्त कर दिया गया है। दुकानें तोड़ने का क्रम जारी है।

मंदिर की करीब दो सौ दुकानें तोड़ी जाएंगी। जब लॉकडाउन के बाद फोरलेन का निर्माण शुरू होने के बावजूद उन्होंने दुकानों को खुद नहीं तोड़ा तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण प्राधिकरण ने इन दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। फोरलेन के निर्माण के जद में गोरखनाथ मंदिर की करीब 200 दुकानों के अलावा निजी लोगों की भी कुछ दुकानें हैं। रखपुर वासियों को गोरखनाथ मंदिर के आसपास घंटों जाम से जूझना पड़ता था। सड़कों पर दुकानदारों का कब्जा रहता था। ऐसे में दुकानों के हटने से

भारत से जुड़ी पॉजिटिव खबरों को खारिज करने में जुटा अंतरराष्ट्रीय-भारतीय मीडिया का एक तबका

बैजयंत जय पांडा
लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं

जब भारत महामारी से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहा है तब मीडिया के लिए जरूरी है कि वह भारत से जुड़े विमर्श की संतुलित तस्वीर पेश करे।

कोरोना वायरस से उपजी महामारी के खिलाफ भारत की जंग एक नए दौर में पहुंच गई है। इस जंग के दौरान यह आम सहमति उभरी है कि देश ने इस आपदा का सामना बहुत सक्षमता और कुशलता से किया है। इसी कारण इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलना भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जैसे सभी प्रमुख जोन में कुछ गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। इससे हालात और सहज होंगे। भारत इस संकट से जिस बखूबी ढंग से निपट रहा है उसकी पुष्टि न केवल डब्ल्यूएचओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिली शाबासी से, बल्कि उन सर्वेक्षणों से भी होती है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के पूर्ण विश्वास और अगाध आस्था को रेखांकित करते हैं।

जमीन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा परिदृश्य कोई हैरानी की बात नहीं। वे लाखों स्वयंसेवक खुद इसकी गवाही दे सकते हैं जो पिछले कई हफ्तों से राहत कार्यों में जुटे हैं। हालांकि इस राह में कुछ दुश्वारियों से भी दो-चार होना पड़ा है, लेकिन देश की व्यापक धारणा यही है कि भारत मिल-जुलकर इस आपदा को मात देकर उबरने में कामयाब होगा। यह सकारात्मक नजरिया उन साक्ष्यों पर आधारित है जो यह रेखांकित करते हैं कि भारत न केवल इस वायरस के संक्रमण को सीमित करने में सक्षम रहा, बल्कि जरूरतमंदों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित कर सका।

भयावह कोहराम मचने की भविष्यवाणी

हालांकि अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय मीडिया का एक तबका अभी भी इस पर अड़ा है कि वह भारत से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर को खारिज ही करता रहेगा। देश को लेकर केवल नकारात्मक एजेंडा आगे बढ़ाने में ही उसकी गहरी दिलचस्पी दिखती है, खासतौर से सरकार के खिलाफ विषवमन करने में। इस विषवमन के लिए स्थापित तथ्यों को भी नजरंदाज किया जा रहा है। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत तक ये मीडिया संस्थान देश में कोरोना के कहर का भयावह कोहराम मचने की भविष्यवाणी कर रहे थे।

उनका जोर इसी पहलू पर था कि जब बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद विकसित देशों ने कोरोना के आगे घुटने टेक दिए तो भारत का भरभराना तय है। तमाम अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में डरावने शीर्षकों के साथ आलेख लिखे गए जो बहुत खौफनाक तस्वीर सामने रख रहे थे। जब संक्रमण के कम प्रसार के साथ ये अनुमान धराशायी होते गए तो इस तबके ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। उसने भारत में परीक्षणों यानी टेस्ट की

कम संख्या को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि हकीकत उसके दावों के उलट थी। वास्तविकता में टेस्टिंग का दायरा भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया और उसमें यह बात भी सामने आई कि यूरोप और अमेरिका के उलट भारतीय इस वायरस के संपर्क में कम ही आए। आइसीएमआर के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रलय के अधिकारियों ने संबंधित आंकड़े भी सामने रखे, मगर मीडिया के एक वर्ग ने अपनी सुविधा और पूर्वाग्रह के कारण इसे खारिज ही किया। जब उसके नकारात्मक सुरों को तथ्यों के जरिये प्रभावी ढंग से शांत किया गया तब इस तबके के बदले रागों से यह आभास हुआ कि अब वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की मुहिम कुछ हफ्तों में दम तोड़ देगी।

मीडिया की जिम्मेदारी नकारात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा ना दे

संकट के समय मीडिया की यही जिम्मेदारी बनती है कि वह वाजिब मुद्दों को उठाए, न कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्रशासन की उपलब्धियों को नकारकर केवल नकारात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे। जब विनाश को लेकर अपना अनुमान साकार होता नहीं दिखा तो नकारात्मक नजरिये से भरे मीडिया ने भारत में इस्लामोफोबिया का शिगूफा छेड़ दिया। इसके लिए उसने तब्लीगी जमात की करतूतों का सहारा लिया।

तब्लीगियों की करतूत के खिलाफ आम जनता के असंतोष को लेकर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस स्थिति का ध्रुवीकरण करने में लगा है। इस वर्ग ने सरकार के उन नियमों का उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा कि जो सभी धार्मिक समूहों पर समान रूप से लागू थे। मीडिया का यह वर्ग प्रधानमंत्री मोदी की उन तमाम अपीलों को भी अनदेखा करता नजर आया जिनमें उन्होंने लोगों से एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि यह वायरस जाति, धर्म और ऐसी किसी अन्य पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करता और इसे हराने के लिए हमारा एकजुट होना जरूरी है। अफसोस की बात है कि भारत को लेकर ऐसा शंकालु नजरिया देश के भीतर और बाहर बसे कट्टर वामपंथी स्वयंभू उदारवादियों में एकसामान भाव से घर करता गया।

भारत के प्रति शंकालु नजरिये वाला मीडिया चीन के प्रति सहानुभूति दर्शाने में कुछ अतिरिक्त प्रयास करता दिखा। इससे उसकी विश्वसनीयता ही घटी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा तो वह लगातार उस पर बहस करता रहा। यह स्थिति तब थी जब मीडिया के सभी वर्गों ने न सही, लेकिन अधिकांश ने शुरुआत में इसे वुहान वायरस नाम ही दिया था। इसे चीनी वायरस कहना नकारात्मकता से भरे मीडिया को नस्लीय टिप्पणी लगा जबकि अतीत में अधिकांश महामारियों को वही नाम दिया गया जिस जगह से उनकी शुरुआत हुई। इनमें जर्मन मीजल्स, जापानी इंसेफेलाइटिस, स्पेनिश फ्लू, इबोला और मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स जैसे तमाम नाम मिसाल हैं।

इसी तरह जब भारत में एक एंटीबायोटिक-रेसिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन मिला तो उसे न्यू डेल्ही मेटलो बीटा-लैकटामेस-1 यानी एनडीएम-1 नाम दिया गया। किसी बीमारी के उद्भव से उसका नाम रखने की पुरानी परिपाटी के उलटे कोरोना मामले में नस्लवाद का मुलम्मा चढ़ा दिया गया। एक बेहद बुनियादी तथ्य को अनदेखा कर अपनी विश्वसनीयता पर ही आघात किया गया।